राष्ट्रीय सहारा
20/2/15

बुंदेलखंड का समाधान-राहत

प्रसंगवश

भारत डोगरा

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैला बुंदेलखंड क्षेत्र गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। अधिकांश किसानों ने एक ही वर्ष (2015) में तीन फसलों की क्षति को झेला है। पहले रबी की अच्छी-भली पक रही फसल फरवरी-मार्च माह की असामयिक भारी वर्षा और ओलावृष्टि से नष्ट हो गई। उसके बाद इतना गंभीर सूखा पड़ा कि खरीफ की फसल तबाह हो गई। वर्तमान में रबी की बुवाई भी बहुत कम हो सकी। अर्थ यह हुआ कि रबी की फसल की कटाई का जब वक्त होगा, उस समय भी लोगों को बहुत कम राहत मिल सकेगी। जब बुवाई ही बहुत कम हुई है, तो उत्पादन भी बहुत कम होगा। तिस पर छोटे व सिंचाई से वंचित किसानों के खेतों में तो और भी कम अनाज होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। अब तो केवल अगली खरीफ से उम्मीद है कि उसे अनुकूल मौसम मिल जाए।

दूसरी बड़ी समस्या पशुओं को बचाने की है। फसल नष्ट हुई तो चारा भी नहीं मिला। भूसे के भाव आसमान छू रहे हैं। धीरे-धीरे पशुओं के लिए पेयजल समस्या जटिल हो रही है। भविष्य में मनुष्यों के लिए भी यह समस्या विकट हो सकती है।

इस बहुत कठिन दौर का सामना करने के लिए बहुत जरूरी है कि सरकारें इस क्षेत्र में राहत पहुंचाने पर समुचित ध्यान दें। मनरेगा व सूखा राहत कार्य बड़े पैमाने पर आरंभ होने चाहिए। फसलों की भारी क्षति का न्यायसंगत मुआवजा मिलना चाहिए। कृषि में रोजगार बहुत कम हैं। अन्य रोजगार गांव के पास उपलब करवाने के प्रयास होने चाहिए। ये ऐसे हों जिनसें गांव में जल-संरक्षण हो, हरियाली बढ़े, मिट्ठा का उपजाऊपन बढ़े तथा पर्यावरण में सुधार हो। जहां स्थिति संभालने की पहली जिम्मेदारी सरकार की है, वहां सामाजिक संगठनों व नागरिक संगठनों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। राहत पहुंचाने के साथ वे क्षेत्र की वैकल्पिक विकास नीतियों के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हाल के वर्षों में विकास की जो नीतियां बनी हैं, उन्होंने जल संकट को और विकट करने तथा मिट्ठी के कुदरती उपजाऊपन को कम करने की भूमिका निभाई है। वन-विनाश व बेतहाशा खनन से बहुत क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर नदियों, अन्य जल स्रोतों व खेती-किसानी की बहुत क्षति हुई।

सिंचाई के नाम पर बहुत महंगी परियोजनाओं को महत्त्व दिया जा रहा है। इनका बजट बहुत अधिक है। भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। पहले से बनी योजनाओं के मूल्यांकन से पता चलेगा कि इनसे लाभ कम मिला विस्थापन व अन्य दुष्परिणाम ज्यादा झेलने पड़े। ऐसी परियोजनाओं के स्थान पर गांव-गांव में छोटे जल संरक्षण व संग्रहण उपायों तथा परंपरागत तालाबों व अन्य जल स्त्रोतों पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इससे टिकाऊ लाभ मिलेगा। रोजगार सृजन भी अधिक होगा। अभी स्थानीय रोजगार का पूर्ण अभाव है। मजदूरी के लिए दिल्ली, पंजाब, फरीदाबाद आदि स्थानों पर रोजगार के लिए बुंदेलखंड से जाने वाले किसानों व खेत-मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस पलायन से अनेक त्रासद घटनाएं जुड़ती जा रही हैं। जगह-जगह मजदूर अनिश्चित स्थिति में रोजगार के लिए भटक रहे हैं-ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों पर, खेत-खलिहानों में। उनकी मजबूर स्थिति का लाभ उठाकर प्रायः उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। कई बार छोटे बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ मजदूरी के लिए आ जाते हैं क्योंकि गांव से उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है।

ऐसी विकट स्थिति में भी रोजगार गारंटी या मनरेगा का कार्यक्रम ठप पड़ा है। आंगनवाड़ी जैसे पोषण कार्यक्रम में गिरावट आई है। किसानों व अन्य गांववासियों को गंभीर संकट का सामना करने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया गया। एक बच्चे से बात करने पर उसने बताया कि वह स्कूल न जाकर जंगल में बेर बीनने जाता है ताकि पेट भर सके। एक गोष्ठी में मैंने कुछ किसानों से बातचीत की। फिर साथ भोजन किया। भोजन में दाल-चावल था। मैंने अपने साथ बैठे किसान से पूछा कि क्या गांव में आजकल दाल भोजन में खाते हो तो उसने कहा कि जब से दलहन की फसल नष्ट हुई है तब से दाल तो अब सपना है। बाजार में दाल जितनी महंगी है, वह हम नहीं खरीद सकते।

इस स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि सूखा व आपदा पीड़ित क्षेत्रों के दुख-दर्द दूर करने को मुख्य प्राथमिकता बनाया जाए। मनरेगा व सूखा राहत कार्य के क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी हो। जरूरी है कि संवेदनाविहीन होती इस व्यवस्था की संवेदना और सार्थकता के प्रयासों को जीवित रखने के प्रयास बढ़-चढ़ कर किए जाएं। शहरों के संवेदनशील लोग सक्रिय हों तो चंद दिनों में करोड़ों रुपये व हजारों टिल अनाज एकत्र कर सभी सूखाग्रस्त जरूरतमंद गांवों में अनाज बैंक व भूसा बैंक स्थापित कर सकते हैं। बुंदेलखंड के कुछ गांवों में जहां यह प्रयास किया गया है वहां गांव में जागरूक गांववासियों की समिति बनाई गई है, जो जरूरतमंद लोगों की सही पहचान कर अनाज बैंक से उन्हें समय पर अनाज उपलब कर सकती है ताकि कोई भूखा न सोए। एक अनाज बैंक 5 क्विंटल अनाज से आरंभ हो तो अच्छा है, पर 2 विंक्टल से भी आरंभ हो सकता हे। 2 विंक्टल गेंहू की कीमत लगभग 3500 रुपये है। इस तरह अपेक्षाकृत कम खर्च पर ही जरूरतमंद गांवों में भूख कम करने के प्रयास से एक मर्यादित व संगठित ढंग से जुड़ा जा सकता है।

जरूरतमंद गांवों में अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों को प्रेरित किया जा सकता हैं कि वे गरीब परिवारों के दुख-दर्द से जुड़े रहें। उनके सहयोग व बाहरी सहयोग से असहाय वृद्ध लोगों के लिए कम्यूनिटी किचन का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें उन्हें दिन में कम से कम एक बार पूरे मान-सम्मान से भोजन पका कर खिलाया जा सके। शहरों में बहुत से प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। सर्दी का मौसम सामने है। उनके लिए ऊनी वस्त्र व कंबल एकत्र करने, आश्रय की व्यवस्था करना है

इसके अतिरिक्त, जरूरतमंद गांवों में अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों को प्रेरित किया जा सकता है कि वे गरीब परिवारों के दुख-दर्द से जुड़े रहें। उनके सहयोग व बाहरी सहयोग से असहाय वृद्ध लोगों के लिए कम्यूनिटी किचन का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें उन्हें दिन में कम से कम एक बार पूरे मान-सम्मान से भोजन पका कर खिलाया जा सके। शहरों में बहुत से प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। सर्दी का मौसम सामने है। उनके लिए ऊनी वस्त्र व कंबल एकत्र करने, आश्रय की व्यवस्था करने या पहले से बने रैन-बसेरों की जानकारी उन्हें देने, कुछ समय के लिए उनके भोजन या चाय की व्यवस्था करने व उन्हें यथासंभव किसी रोजी-रोटी के अवसर से जोड़ने के प्रयास हों तो इससे उन्हें सहायता मिलेगी।